* 19th Year
* Issue: 216
* 10.12.2025 (WEDNESDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

लोकसभा और राज्यसभा में गरमागरम बहस, अमित शाह और खरगे में वार-पलटवार

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): चुनाव सुधार आज लोकसभा में राजनीतिक रूप से गरमागरम बहस का केंद्र बिंदु रहा। सदन ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया है। इस चर्चा में चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव प्रचार खर्च में पारदर्शिता, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उज़्मीदवारों के प्रवेश पर अंकुश, इलेज़्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं, राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर चर्चा हुई जहां अमित शाह और मल्लिकार्जुन खरगे के बीच वार-पलटवार का दौर देखने को मिला। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक चलेगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को 'वोट चोरी' को "सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य" करार दिया और आरोप लगाया कि सज़ापक्ष में बैठे लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं तथा 'आइडिया ऑफ इंडिया' (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रहे हैं।

उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सज़ापक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निर्वाचन आयोग तथा दूसरी संस्थाओं पर कज़्ज़ा करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को मशीन से पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलज़्ध कराई, मतदान के समय की सीसीटीवी फुटेज दी जाए तथा ईवीएम संरचना के बारे में जानकारी दी जाए।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को लोकसभा में दावा किया कि निर्वाचन आयोग के पास विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का कोई कानूनी आधार नहीं है और इस प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह भी कहा कि 2023 के निर्वाचन कानून में बदलाव कर मुज़्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश को शामिल किया जाए, फिर से मतपत्रों से चुनाव कराए जाएं तथा चुनावों से पहले लोगों के खातों में नकदी भेजने के चलन पर अंकुश लगाया जाए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संजय जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि यह देश बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद इन्हें

निकाल बाहर किया जाएगा। उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बिहार एसआईआर में 35 लाख लोग ऐसे मिले, जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं।

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि चुनाव सुधार तभी होगा, जब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होगा और इसे पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नियुक्ति के तरीके बदलने की जरूरत है। उन्होंने ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की भी मांग की। चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि निर्वाचन आयोग को निर्भीक होने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रत्येक भारतीय को मतदान का अधिकार है और नागरिकता तय करने का अधिकार आयोग को नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख सहयोगी दलों तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) ने मंगलवार को कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग की उपलज़्धियों को स्वीकारने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के बजाय आयोग और उसकी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद पर निशाना साधने का आरोप लगाया।

इंडिगो एयरलाइन्स के परिचालन में व्यवधान से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर सरकार की तरफ से कदम उठाये जाने का आश्वासन देते हुए नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि किसी भी एयरलाइन को यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नायडू ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, "देशभर में विमान परिचालन में खामियों से यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए इंडिगो के खिलाफ कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी।"

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान को लेकर मंगलवार को आश्वासन दिया कि क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राशि दी जाएगी। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के भुमारे एस. आसाराम के प्रश्न का उज़र देते हुए यह बात कही।

राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना से देश को जोड़ने वाला "अमर स्तुति गीत" बताते हुए सभी से एकता और राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर उच्च सदन में चर्चा से पहले सभापति ने कहा कि यह गीत उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की याद दिलाता है, जो इसे गाते हुए फांसी के तज़्ते तक निर्भीकता से पहुंचे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के दो टुकड़े न किए जाते तो देश का विभाजन भी नहीं होता। शाह ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए उज़्मीद जतायी कि इस चर्चा के माध्यम से देश के बच्चे, युवा और आने वाली पीढ़ी यह बात समझ सकेंगे कि वंदे मातरम् का देश को स्वतंत्रता दिलाने में ज़्या योगदान रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा नेताओं पर जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 'वंदे मातरज़्' के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का निर्णय केवल नेहरू का नहीं था, बल्कि यह निर्णय महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य नेताओं की सहमति से लिया गया था।

ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो जनता को परेशान करे-नरेंद्र मोदी

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): बिहार विधानसभा चुनावों में गठबंधन की शानदार जीत के लिए मंगलवार को सज़ारूढ़ एनडीए के सभी सांसदों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए काम करने का निर्देश दिया। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में सुधारों पर ज़ोर दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के बीच आई है। बिहार चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों को देश, अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अपने राज्यों के लिए ज़्या करना चाहिए, इस बारे में बेहतरीन दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन दिया। मैं एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुधारों पर बहुत ज़ोर दिया है। रिजिजू ने कहा कि उनका आशय देश के आम लोगों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए सुधारों से था। हर क्षेत्र में सुधार। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को सरकार से कोई परेशानी न हो। नियम और कानून महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल लोगों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लोगों पर बोझ नहीं होना चाहिए। इंडिगो एयरलाइन के परिचालन में लगातार हो रही देरी और रद्दीकरण का सिलसिला जारी है, जबकि संकट आठवें दिन भी जारी है। मंगलवार को भी जारी अफरा-तफरी के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गईं। इस बीच, सरकारी प्रतिनिधि और डीजीसीए के अधिकारी आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर से मिलकर स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं।

नगालैंड की परंपराएं भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूत करती हैं : अमित शाह

नगालैंड ०९/१२ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नगालैंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि पूर्वोज़र राज्य की जीवंत परंपराएं और वहां के लोगों की जुझारू भावना राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूत करती है। नगालैंड का गठन एक दिसंबर, 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में किया गया था। तब से एक दिसंबर को प्रतिवर्ष नगालैंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।गृह मंत्री शाह ने एज़्स पर एक पोस्ट में कहा, नगालैंड की बहनों और भाइयों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की जीवंत परंपराएं और इसके लोगों की जुझारू भावना हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूती प्रदान करती है।

माइक्रोसॉफ्ट करेगा 1.57 लाख करोड़ का बड़ा निवेश, भारत में बनेगा एआई हब, मोदी से मिले नडेला का ऐलान

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने मंगलवार को घोषणा की कि वह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कौशल निर्माण हेतु 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जो एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद एज़्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की। नडेला ने ट्वीट किया भारत के एआई अवसर पर प्रेरक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए, माइक्रोसॉज़्ट भारत के एआई-प्रधान भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद के लिए एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश - 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर - करने की प्रतिबद्धता जता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नडेला की यह मुलाकात इस साल की शुरुआत में उनके उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी अगले दो वर्षों में भारत में ज़्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जिसमें नए डेटा सेंटर की स्थापना भी शामिल है। कंपनी अगले पाँच वर्षों में देश में 1 करोड़ लोगों को एआई कौशल प्रशिक्षित करने में भी मदद करेगी। अपने माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के बेंगलुरु चरण में नडेला ने कहा कि भारत एआई नवाचार में तेज़ी से अग्रणी बन रहा है और देश भर में नए अवसर पैदा कर रहा है।

ममता बनर्जी का केंद्र पर हल्ला बोल, कहा- फंड रोकने से नहीं रुकेगा बंगाल का विकास

कोलकाता ०९/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है और सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से चलाना जारी रखेगी। उन्होंने एनआरसी और सीएए के प्रति अपने कड़े विरोध को भी दोहराया और घोषणा की कि बंगाल कभी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा कि हमें केंद्र से किसी मदद की आवश्यकता नहीं है; हम सभी योजनाएँ स्वयं चला रहे हैं। परसों, उन्होंने (केंद्र ने) हमें एक नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने को कहा था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपके नोटिस का कोई महत्व नहीं है। बंगाल 100 दिनों का कार्य कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा।मुज़्यमंत्री ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया और कहा कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा। न एनआरसी, न सीएए, हम इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र बचाएँगे और बंगाल को बचाएँगे। मनरेगा फंड के निलंबन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए, मुज़्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ममता ने कहा, उन्होंने 100 दिनों के काम के लिए धनराशि रोक दी। मैंने प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और धनराशि फिर से शुरू करने की अपील की।

राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे ने किया पलटवार, कांग्रेस नेता के एक-एक आरोपों पर दिया करारा जवाब

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में संवैधानिक संशोधनों के ज़रिए कई संस्थाओं को नष्ट कर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान संशोधनों के ज़रिए राष्ट्रपति के पद को भी निष्क्रिय बना दिया गया था। संसद के निचले सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि मौजूदा संस्थाओं पर आरएसएस का कज़्ज़ा हो गया है। दुबे ने 1976 की स्वर्ण सिंह समिति का हवाला दिया, जिसके कारण 42वां संशोधन हुआ था। उन्होंने कहा कि इसने राष्ट्रपति के अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने गांधी के दावों की आलोचना की और संस्थाओं और नियुक्तियों को प्रभावित करने के कांग्रेस के अपने इतिहास का हवाला दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनी और उन्होंने सभी संस्थाओं को ख़त्म कर दिया, जैसा कि वे आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में राष्ट्रपति का ज़िक्र 121 बार आता है, और आपको हैरानी होगी कि एक संशोधन के साथ कांग्रेस ने राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दीं। राष्ट्रपति रबर स्टैंप बन गए। कैबिनेट जो कहेगी, राष्ट्रपति जो कहेंगे, वही होगा, संस्था ख़त्म हो गई।

दूबे का यह बयान राहुल गांधी द्वारा चुनाव सुधारों पर सदन को संबोधित करने के ठीक बाद आया है। गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की संस्थाओं पर कज़्ज़ा किया जा रहा है, और मैं इस मुद्दे पर आऊँगा कि चुनाव आयोग पर भी कज़्ज़ा किया जा रहा है। गांधी ने कहा था, खुफिया एजेंसियों पर कज़्ज़ा, यहाँ गृह मंत्री बैठे हैं, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग पर कज़्ज़ा, और ऐसे नौकरशाहों की व्यवस्थित तैनाती जो उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं और विपक्ष और आरएसएस का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं। विपक्षी नेता के दावों को खारिज करते हुए, निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की थी, जिसमें भारत के मुज़्य न्यायाधीश की सामान्य नियुक्ति को उलटना भी शामिल था। दुबे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इसमें वोट चोरी की, रायबरेली चुनाव जीता, और जब अदालत का फैसला आया, तो पार्टी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उन्होंने 3 न्यायाधीशों को दरकिनार कर एक ऐसे मुज़्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जो 8.5 साल से अपने पद पर था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान संशोधनों के ज़रिए राष्ट्रपति के पद को भी निष्क्रिय बना दिया गया था। संसद के निचले सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि मौजूदा संस्थाओं पर आरएसएस का कज़्ज़ा हो गया है।

विविध समाचार

कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बिहार राज्य में तीन नए विभागों के गठन की मिली मंजूरी

०९/१२ (संवाददाता): नई सरकार के गठन होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। जिसमें तीन नये विभागों के गठन के साथ ही षष्ठम वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में पांच फीसदी की वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार पंचम वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ता में आठ फीसदी की वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है।

विदित हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर वादे किए थे। जिसको लेकर वह लगातार प्रयासरत हैं। अपने वादे की दिशा में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय ली है। जिसमें तीन नये विभाग के गठन की स्वीकृति भी शामिल है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए आमजन के प्रति अपने दायित्वों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए वर्तमान में कार्यरत 45 विभागों के अतिरिक्त 03 (तीन) नये विभागों का गठन किया जा रहा है। जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है। उन्होंने बताया कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने तथा उन्हें कुशल कौशल बनाने हेतु एक नया विभाग युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में कार्यरत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित

कार्यों को समाहित कर एक नये विभाग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जा रहा है। वहीं राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को और विस्तृत करने तथा वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से वर्तमान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए एक नये विभाग सिविल विमानन विभाग का गठन किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तीन विभागों के नाम बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति दी गई है।

एसीएस ने बताया कि गया जी एवं मुंगेर जिला प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं के साथ-साथ सामरिक एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गया जी शहर भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली होने, पितृपक्ष मेला तथा बौध महोत्सव आयोजित होने के कारण सालों भर देशी एवं विदेशी अतिथियों से भरा रहता है। इसी प्रकार मुंगेर जिला में कई प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान यथा- जमालपुर रेल इंजन कारखाना, ब्रिटिश गन फैक्ट्री एवं अन्य आई0 टी0 सी0 फैक्ट्री स्थापित है। युद्ध/ शत्रु हमले की स्थिति में इन जिलों को लक्षित कर देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों जिला में प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखकर नागरिक सुरक्षा कोर के लिये पूर्व से स्वीकृत 28 जिलों के अतिरिक्त गया जी एवं मुंगेर जिला को भी नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया जाना आवश्यक है। इसको देखते हुए गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने तथा उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाईयों के लिए कुल 14 (चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पटना जू में पार्क प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, आयोजन, अनुदान एवं दान दत्तक निधि सहित अन्य संसाधनों को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार बिहार में पूर्व से घोषित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन का गठन किया गया है। इसके लिए 15 करोड़ की राशि को कॉरपस फंड के गठन की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक जुलाई से वेतन वृद्धि होती है। अगर कोई कर्मी 30 जून को सेवानिवृत होता है तो उसे भी पेंशन में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। इसी तरह बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन वेबिनार और ऑफलाइन सेमिनार के माध्यम से निवेशक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों, लाभुकों एवं व्यवसायिक लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुम्बई ने राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एमओयू करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। एसीएस ने बताया कि बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति (संशोधित) नियमावली 2025 लागू की गई है। अब लेपर प्रभावित व्यक्तियों को भी अनुज्ञप्ति मिलेगी। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना संचालित है। इस योजना के तहत महिला भिक्षुकों के लिए शांति कुटिर एवं पुरुष भिक्षुकों के लिए सेवा कुटिर गृह का संचालन किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के नियम 6 (2) (ख) में उल्लेखित संबंधित शब्दों को प्रतिस्थापित करते हुए निरूपण संशोधित किया जाता है। इसके बाद कोढ़ या पागल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा।कैबिनेट ने नगर निकायों के पास विद्युत कंपनियों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए, कहा-कला हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का सेतु है

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि कला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे अतीत की स्मृतियों, वर्तमान की अनुभूतियों और भविष्य की आकांक्षाओं का जीवंत पुल है। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने प्राचीन काल से ही चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने कहा कि कला न केवल संस्कृति से जोड़ती है, बल्कि लोगों के बीच सामाजिक एवं भावनात्मक संबंधों को भी मजबूत बनाती है।

राष्ट्रपति ने भारतीय हस्तशिल्प की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे कारीगरों की अटूट प्रतिबद्धता और सृजनशीलता ने इस विरासत को सदियों से जीवित रखा है। समय के साथ तकनीक और मांग बदलती रहीं, पर कारीगरों ने अपनी मूल भावना और मिट्टी की महक को हर रचना में संजोए रखा।

उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प केवल सांस्कृतिक पहचान का दर्पण ही नहीं, बल्कि देश की आजीविका का भी एक मज़बूत स्तंभ है। यह क्षेत्र आज 32 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, जिनमें अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों से आते हैं। रोजगार एवं आय का यह विकेंद्रीकरण समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी हस्तशिल्प की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूप से यह क्षेत्र वंचित तबकों के लोगों की आजीविका का आधार रहा है। उन्होंने गर्व के साथ उल्लेख किया कि हस्तशिल्प क्षेत्र में 68 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं, और इस क्षेत्र का विकास महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को और गति देगा।

पर्यावरणीय दृष्टि से हस्तशिल्प की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह उद्योग स्थानीय एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होने के कारण अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल है। दुनिया भर में टिकाऊ जीवनशैली की बढ़ती आवश्यकता के बीच, भारतीय हस्तशिल्प वैश्विक स्तर पर स्थायित्व का मजबूत उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को मिल रहे जीआई टैग को अंतरराष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण साधन बताते हुए सभी हितधारकों से अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 'एक ज़िला, एक उत्पाद' (ह्रष्ठह्रक्क) पहल ने भी क्षेत्रीय हस्तशिल्प की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दी है।

अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारतीय कारीगरों के ज्ञान, समर्पण और परिश्रम ने विश्वभर में भारतीय हस्तशिल्प की एक अलग पहचान स्थापित की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस क्षेत्र में मांग और संभावनाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जो युवा उद्यमियों और डिज़ाइनरों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है।

कब सुधरेंगे इंडिगो के हालात? एयरलाइन की आज 400 से अधिक उड़ानें रद्द

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): इंडिगो द्वारा रद्द की गई उड़ानों की भारी संख्या ने मंगलवार को पूरे भारत में हवाई यात्रा को प्रभावित करना जारी रखा, सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाईअड्डा अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवधान के कारण अब तक देश भर में 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (ढ्ढत्रढ्ढ) पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जहाँ इंडिगो की 152 उड़ानें रद्द होने की पुष्टि हुई, जिनमें 76 आगमन और 76 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं, अधिकारियों ने बताया। दक्षिणी हवाईअड्डों पर भी रद्दीकरण का असर दिखा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर, 58 आगमन और 63 प्रस्थान वाली उड़ानें रद्द कर

दी गईं, हवाईअड्डा प्राधिकरण ने घोषणा की कि अगला अपडेट शाम 6 बजे के बाद जारी किया जाएगा। चेन्नई में भी महत्वपूर्ण व्यवधान की सूचना मिली, जहाँ दिन भर में 18 प्रस्थान और 23 आगमन वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (क्रत्रढ्ढ) ने 44 प्रस्थान और 14 आगमन वाली उड़ानों के रद्द होने की पुष्टि की।

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अपेक्षाकृत कम रद्दीकरण दर्ज किए गए, एक आगमन और तीन प्रस्थान रद्द होने की सूचना दी गई, जबकि कुछ उड़ानों के निर्धारित समय पर संचालित होने की पुष्टि की गई। अहमदाबाद में हवाई अड्डे के सुबह 8 बजे के अपडेट में 16 रद्दीकरणों की पुष्टि हुई, जिनमें नौ आगमन और सात प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनल या हवाई अड्डे पर कोई समस्या नहीं थी और सभी यात्रियों को सहायता प्रदान की जा रही थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 9:30 बजे के अपडेट के अनुसार, 31 उड़ानें रद्द हुईं, जिनमें 14 आगमन और 17 प्रस्थान शामिल हैं।

नित्यानंद राय का दावा, 2036 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि अगले डेढ़ दशक में भारत की बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रित कल्याणकारी उपायों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है। कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा लोकसभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने की उम्मीद है, और कहा कि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की आबादी में तेज वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और

डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां पेश करेगी। इन उभरती चिंताओं के जवाब में, राय ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) को लागू कर रहा है, जो 1 अप्रैल, 2021 से संचालित एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ स्थानीय निकायों और बड़े पैमाने पर समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करके उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना है। वृद्धजनों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण, वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।

चुनाव चोरी का मुद्दा अहम, लोकसभा में राहुल गांधी का सवाल

नयी दिल्ली ०९/१२ (संवाददाता): संसद में चुनाव सुधारों पर बोलते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि वह चुनाव आयोग के प्रमुख और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए ज़िम्मेदार पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर इतनी आमादा क्यों है। राहुल गांधी ने पूछा कि मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से क्यों हटाया गया? क्या हमें मुख्य न्यायाधीश पर विश्वास नहीं है?

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश 1.5 अरब लोगों का तानाबाना है जो वोट के माध्यम से बुना हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालयों, खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग सत्तापक्ष में बैठे लोगों के साथ

मिलीभगत करके फैसले कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 2023 में कानून बदल दिया ताकि किसी चुनाव आयुक्त को उसके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया।

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार लंबे प्रचार अभियान के लिए समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी खादी पर इतना ज़ोर क्यों देते थे? ऐसा क्यों था कि उन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को खादी की अवधारणा के इर्द-गिर्द गढ़ा, और ऐसा क्यों था कि उन्होंने सिर्फ़ खादी ही पहनी? क्योंकि खादी सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं है। खादी भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है; यह कल्पना है, यह भावना है, यह भारत के लोगों की उत्पादक शक्ति है। आप जिस भी राज्य में जाएँगे, आपको अलग-अलग कपड़े मिलेंगे। हिमाचली टोपी, असमिया गोमछा, बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, नागा जैकेट। और आप पाएँगे कि ये सभी कपड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कपड़े सुंदर हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से देखें, तो आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक में हज़ारों छोटे धागे एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी धागा दूसरे धागे से बेहतर नहीं है। धागे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। धागे आपको गर्म नहीं रख सकते। लेकिन जब वे एक कपड़े के रूप में एक साथ आते हैं, तो वे आपको गर्म रख सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं, और आपके दिल में जो है उसे व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह, हमारा राष्ट्र भी 140 करोड़ लोगों से बना एक ताना-बाना है, और ये ताना-बाना वोट से बुना गया है। ये सदन जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, लोकसभा, राज्यसभा, देशभर की विधानसभाएँ, देशभर की पंचायतें, इनमें से कोई भी अस्तित्व में नहीं होता अगर वोट न होता।

उन्होंने कहा कि यह विचार कि भारत संघ का हर धागा, हर व्यक्ति समान है, मेरे आरएसएस मित्रों को परेशान करता है। वे इस ताने-बाने को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वे इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश के ताने-बाने में हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वह किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो, समान होना चाहिए, क्योंकि वे मूलतः समानता में विश्वास नहीं करते। वे पदानुक्रम में विश्वास करते हैं, और उनका मानना है कि उन्हें उस पदानुक्रम में सबसे ऊपर होना चाहिए।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

क्या आप भी हैं कॉफी के एडिक्ट, तो ऐसे छुड़ाएं ये आदत!

बहुत से लोगों को कॉफी यानि कैफीन का नशा होता है. कुछ लोग चाहकर भी कैफीन की लत को छोड़ नहीं पाते. आज हम आपको बता रहे है कैसे आप आसानी से कुछ टिप्स अपनाकर कैफीन की लत से छुटकारा पा सकते है.

डीप ब्रीथ प्रैक्टिस- कैफीन विड्रावल सिम्टम से फाइट करने के लिए डीप ब्रीथ प्रैक्टिस करे. लंबी-लंबी गहरी सांसे लेने से कैफीन की स्ट्रांग क्रेविंग, एंग्जाइटी और बेचैनी को भी खत्म किया जा सकता है.

खूब पानी पीएं- कैफीन के एडिक्शन से बचने का बेहतर तरीका है कि पानी खूब पीएं. इससे आपकी क्रेविंग भी कम होगी. रोजाना पानी की अधिक मात्रा पीने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आपकी बॉडी को ये हाइड्रेट रखेगा.

बेहतर नींद लें- अच्छी नींद से भी कैफीन की लत छुड़ाने में मदद मिलती है. लेकिन कम नींद लेने से आपकी कैफीन छुड़ाने की लत पर बुरा असर पड़ता है. हेल्दी स्लिप हैबिट अपनाएंगे तो धीरे-धीरे कैफीन की क्रेविंग कम होने लगेगी.

ग्रीन टी- कॉफी के बदले ग्रीन टी लेने की कोशिश करें. इसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिंस को बाहर निकालते हैं. ग्रीन टी पीने से ओवरऑल कैफीन इंटेक कम हो जाता है. कॉफी के बजाय दिनभर मे 3 से 4 कप ग्रीन टी पीएं.

कुछ अन्य टिप्स-

रोजाना सुबह एक्सरसाइज करें हेल्दी जूस का सेवन करें प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर सप्लीमेंट्स या फूड का सेवन करें जिनसेंग हर्ब का इस्तेमाल करें ये कैफीन की लत को छुड़ाने में मदद करेगा.

मेकअप उतारने के कुछ आसान नेचुरल नुस्खे

ऑफिस, पार्टी, फंक्शन से आने के बाद जितना जरूरी कपड़े बदलना होता है उतना ही जरूरी मेकअप उतारना होता है। इससे आपकी चेहरे की स्किन के रोम छिद्र भी खुल जाते है और पूरे दिन की धूल मिट्टी भी साफ हो जाती है। मेकअप उतारने के लिए आज बाजार में ढेरों प्रोडक्ट मौजूद है। लेकिन इन सब के ना होने के बाद भी आप अपना मेकअप उतार सकती है वो भी सुरक्षित तरीको से। आज हम आपको बताने जा रहे है कुछ ऐसे ही सरल तरीके जिनकी मदद से आप अपना मेकअप तो उतार ही सकती है साथ ही इससे आपकी त्वचा में निखार और चमक भी बरकरार रहेगी ।

दही

दही के फायदे तो हम पहले से ही जानते हैं दही खाने और चेहरे पर लगाने से त्वचा में चमक आती है लेकिन क्या आप जानती है कि इसे मेकअप उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, दही एक मेकअप रिमूवर भी है ? इसके लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह से फेंट ले ? फिर इसमें कॉटन बॉल डुबोकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ने के बाद जब मेकअप पूरी तरह निकल जाए तो चेहरा पानी से धो लें।

बेबी शैम्पू

बेबी शैम्पू से भी मेकअप रिमूव कर सकते है। एक कप पानी में आठ टी-स्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल और आधा टीस्पून बेबी शैम्पू मिलाकर एक बोतल में भरकर आप इसे फ्रीज कर सकती है और जरूरत के वक्त इसे मेकअप रिमूव के प्रयोग में ला सकती है।

कच्चा दूध और बादाम तेल

एक टेबलस्पून कच्चे दूध में बादाम के तेल की कुछ बूंदे मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मेकअप छुड़ाएं। यह आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। इससे आपकी त्वचा मुलायम होती है।

जोजोबा एंड विटामिन ई ऑयल:

विटामिन ई त्वचा को मुलायम बनाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। जोजोबा ऑयल और एक विटामिन ई कैप्सूल को मिलाकर कांच की बोतल में रख दें। इससे वाटर प्रूफ मस्कारा लिक्विड आई लाइनर भी बिना ज्यादा मेहनत के रिमूव कर सकती है।

नारियल तेल

आपने कोकोनट ऑयल का प्रयोग मॉइश्चराइजर, लिप बाम की तरह किया होगा। इसके साथ आप मेकअप रिमूवर के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकती है। थोड़ा-सा नारियल तेल हथेली पर लेकर इसे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है और दाग-धब्बों को दूर करता है।

आंखों को इस तरह से लाभ पहुंचाता है ये सेब!

सेब के तो आपने बहुत फायदे सुने होंगे लेकिन क्या आप जानते है ये आंखो के लिए भी बहुत फायदेमंद है. आज आचार्य बालकृष्ण जी बता रहे है सेब के जरिए कैसे आंखो की समस्याओं को दूर रखा जा सकता है.

आंखों की परेशानी में सेब- जब आंखो में सूजन हो, लाली हो या फिर कोई इंफेक्शन हो तो कच्चे सेब को आग में भूनकर इसकी पोटली से आंख की सिकाई करें. इससे एलर्जी और आंख की बाकी समस्याओं से निजात मिलेगी.

सेब की चाय- सेब की चाय बनाने के लिए कच्चे सेब के टुकड़े सुखा लें. सुखाने के बाद इसमें तुलसी का पत्ता, पुदीना, काली मिर्च और लौंग मिलाकर उबाल लें. ये चाय का बेहतर विकल्प है. सेब की चाय सर्दी और खांसी में आराम देती है.

बिच्छू डंक में सेब- सेब की पत्तियां बिच्छू डंक में बहुत ही अच्छा काम करती हैं. सेब की 10 ग्राम पत्तियों को 400 ग्राम पानी में मसलकर छानें. बचा हुए पानी जब 100 ग्राम रह जाए तो उसमें सेंधा नमक डालकर इसका सेवन करें.

सेब के पत्ते के पानी में सेंधा नमक घोलकर 4 से 5 बूंदें बिच्छू के डंक के घाव को भरने के लिए बिच्छू जिस हिस्से में काटा है उसकी दूसरी तरफ कान में डाल दीजिए, आराम मिलेगा.

सर्दियों में हरी मटर खाने के है ये बेमिसाल फायदे, जानिए

यूं तो सभी सब्जियों के अपने अलग-अलग फायदे है तथा सभी सेहत के लिए लाभदायक होती है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कि मौसम के अनुसार खाने से ही फायदा करती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में हरी सब्जियां ज्यादा मिलती है।

मटर सर्दियों की सबसे अहम सब्जियों में से एक होती है। बहुत कम ही लोग होते है जो मटर के गुणों के बारे में जानते हैं। इसे खाने से आप कई तरह की गंभीर बीमारियों से भी बच सकते है। इसका रोजाना सेवन करने से कैंसर, मोटापा से बचाव होता है। जानिए इसको सेवन करने के फायदों के बारे में।

कैंसर से करें बचाव

मटर के सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है। हर रोज इसे खाने से शरीर से कैंसर के घातक एलीमेंट दूर हो जाते है।

मोटापा से दिलाए निजात

यह फाइबर से भरपूर होती है। यह हमारी बॉडी को एनर्जी देने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जिससे कि बॉडी से फैट की मात्रा को भी कम करता है।

मधुमेह

मटर खाने से मधुमेह नहीं होता है। मटर शरीर में खून के स्तर को नियंत्रित करता है। जिससे की डायबिटीस की समस्या नहीं होती है।

कोलेस्ट्रॉल को करें कम

मटर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती है। मटर खाने से बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ता नहीं है। जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है।

उंगलियों की सूजन को करें कम

सर्दियों के दिनों जिन लोगों की उंगलियां सूज जाती है उनके लिए मटर काफी लाभदायक सिद्ध होता है। मटर के काढ़े के अंदर उंगलियां डुबोने से सूजन कम हो जाती है।

रखें जवां

मटर खाने से आपकी त्वचा लंबे समय के लिए जवान रहती है। इसमें फ्लैवानोइड्स, फ्लाइटोन्यूट्रिएंस, कैरोटिन जैसे एंटी ऑक्सीडेंट होते है।

याददाश्त बढ़ाएं

मटर का सेवन करने से याददाश्त बढ़ती है और यह फेफड़ों संबंधी बीमारियों को भी दूर करती है।

हड्डियों को रखें मजबूत

मटर में विटामिन होता है जो की हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों के लिए असरदार होती है।

चेहरे की झाइयों को करें कम

मटर सेहत के लिए तो लाभदायक है ही साथ ही साथ सौंदर्य के लिए भी असरदार साबित होती है। मटर के आटे का उबटन चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयां कम होती है।

टॉन्सिल की दिक्कत से जुड़ी हुई हैं ये समस्याएं भी

टॉन्सिल होने पर गले के दोनों ओर सूजन आ जाती है। शुरुआत में मुंह के अंदर गले के दोनों ओर दर्द महसूस होता है और बार-बार बुखार भी आता है। टॉन्सिल्स सामान्य से ज्यादा लाल हो जाते है लेकिन क्या आप जानते है कि टॉन्सिल के कारण आपको कई अन्य तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। कुछ ऐसी ही समस्याओं पर एक नजर-

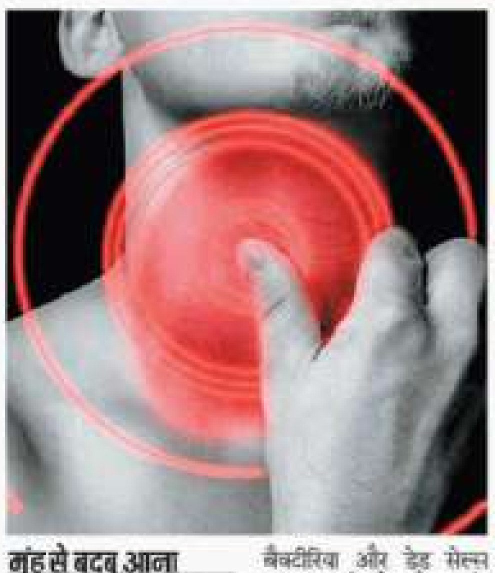

मुंह से बदबू आना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार, दुनिया की आधी आबादी मुंह की सफाई न करने के कारण मुंह की बदबू से ग्रस्त हैं। लेकिन टॉन्सिल की समस्या होने पर भी सांसों से बदबू आने लगती है। टॉन्सिल ग्लैंड दरारों से भरा होता है जहां बैक्टीरिया और डेड सेल्स अटक जाते है और इनके कारण मुंह से बदबू आने लगती है।

खर्राटों की समस्या

गले में बढ़े हुए टॉन्सिल के कारण आपको खर्राटे की समस्या हो सकती है। अमेरिकन अकादमी ऑफ ओटोलर्यनोलॉजी के अनुसार, बढ़े हुए टॉन्सिल से खर्राटों की समस्या हो सकती है। जब बार-बार होने वाले संक्रमण के कारण टॉन्सिल का आकार बढ़ने लगता है तो गले में हवा के बहाव में रुकावट आने लगती है। जिससे खर्राटे की समस्या होती है।

साइनस इन्फेक्शन

बढ़े हुए टॉन्सिल से बार-बार साइनस और कान में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। ऐसा नाक और कान को जोड़ने वाली नली बंद हो जाने से होता है और कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो जाता है। कभी-कभी कान से पस बाहर आने लगता है। इससे सुनने की क्षमता कम होने लगती है।

सिरदर्द की समस्या

बढ़े हुए टॉन्सिल के कारण सोते समय सांस लेने में भी परेशानी होती है। नींद में इस तरह का खलल आने से ब्रेन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इसकी कमी से रक्त-वाहिनियों का आकार बढ़ जाता है और सिरदर्द होने लगता है।

प्लास्टिक के डिब्बों को साफ करने के लिए आजमाएं ये तरीके

आज के समय में ज्यादातर लोग स्टील और एल्युमिनियम के डिब्बों की जगह प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करना पसंद करते है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये डिब्बे काफी हल्के होते है और इनके टूटने का डर भी नहीं होता। आजकल बाजार में ऐसे कंटेनर भी आ गए है जिन्हें माइक्रोवेव में भी रखा जा सकता है। इनमें खाना फ्रेश बना रहता है और साथ ही यह देखने में काफी आकर्षक भी होते है। हालांकि प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए साथ ही इनकी सफाई का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, वरना ये नुकसानदेह हो सकते है।

कई बार प्लास्टिक के डिब्बों को अच्छे से साफ न करने पर उनमें से बदबू आने लगती है और चिकनाहट बनी रह जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आपको इन्हें साफ करने का सही तरीका पता हो-

1. बदबू दूर करने के लिए

अगर आपके प्लास्टिक के बॉक्स से बदबू आ रही है तो यह घरेलू उपाय आपके लिए उपयोगी होगा। एक बाल्टी गर्म पानी ले लें और उसमें तीन चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। प्लास्टिक के इन बॉक्स को बाल्टी में डाल दें। कुछ देर बाद इन्हें निकालकर साफ करें। आप चाहें तो बाल्टी के इस पानी में नींबू का रस और सिरका भी मिला सकते है।

2. जिद्दी दाग

अगर आपके प्लास्टिक के डिब्बों पर जिद्दी दाग है तो उन्हें साफ करने के लिए क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहेगा। दाग लगे डिब्बों को ब्लीच के इस मिश्रण में डालें। कुछ देर बाद इन्हें निकालकर साबुन से धो लें। दाग दूर हो जाएंगे।

3. रख-रखाव

अगर आप नहीं चाहते कि प्लास्टिक के डिब्बों से बदबू आए तो एक बात का ख्याल हमेशा रखें कि इनमें लंबे समय तक खाना न रखें। साथ ही हर कंटेनर माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, यह जरूरी नहीं। ऐसे में बिना जांचें इन्हें माइक्रोवेव में न रखें।

सर्दियों में त्वचा को यूं बनाएं खूबसूरत!

बदलते मौसम के साथ ही स्किन की खास देखभाल करना और भी जरूरी हो जाता है. स्किन में निखार लाने के लिए क्रीम और सीरम लगाने के अलावा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी है जो आपकी त्वचा को चमकदार और खूबसूरत बना सकते है. काया लिमिटेड की प्रमुख मेडिकल सर्विसेज एंड आर एंड डी संगीता वेलासकर ने अपनी खूबसूरती को लेकर विशेष रूप से सजग रहने वाली महिलाओं के लिए कुछ सुझाव दिए है.

कोलेजन हमारी कोशिकाओं से निकलने वाले प्रोटीन है जो त्वचा को एक साथ जकड़ कर रखने में मददगार होता है. कोलेजन त्वचा में कसाव लाकर जवां लुक देता है. जब हम युवा होते हैं तो हमारी त्वचा मोटी और कोमल होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन बनना कम हो जाता है, जिसके चलते झुर्रियां पड़ने लगती है और जो कोलेजन मौजूद होते हैं वह भी सूर्य की हानिकारक किरणों के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोलेजन युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करें. इससे आपकी त्वचा में कसाव और चमक आएगी और झुर्रियां और महीन रेखाएं खत्म हो जाएंगी. एसेटिल हेक्सापेप्टाइड-8 एक प्रकार से न्यूरोपेप्टाइड होता है, जिसका इस्तेमाल मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है.

यह झुर्रियां और महीन रेखाएं भी दूर करता है, इसलिए एसेटिल हेक्सापेप्टाइड-8 युक्त सौंदर्य उत्पाद का इस्तेमाल करें. शरीर में कोलेजन बनना कम होने से झुर्रियां पड़ने लगती है, जबकि अत्यधिक कोलेजन से त्वचा ढीली होने लगती है.

ऐसे में हायलूरोनिक युक्त उत्पाद का प्रयोग त्वचा में एसिड कोलेजन के स्तर को उचित मात्रा में बनाए रखता है और त्वचा में नमी बरकरार रखता है. इससे आपकी त्वचा जवां नजर आती है. ग्लाइकोलिक एसिड गन्ने के रस से निकलता है. यह अल्फा हाइड्रॉक्सी समूह के सबसे छोटे अणुओं में से एक है. यह त्वचा में गहराई से समाकर प्रभावकारी असर दिखाता है. ग्लाइकोलिक एसिड युक्त उत्पाद के इस्तेमाल से काले धब्बे, मुंहासे, झाइयां, ऑयलीनेस दूर होता है और आपकी त्वचा पहले से ज्यादा जवां और निखरी नजर आती है.

इस छोटी सी ट्रिक से मिलेगा अनचाहे बालों से छुटकारा

यूं तो महिलाएं बॉडी के अनचाहे बालों से परेशान रहती ही है लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी होती है चेहरे पर आने वाले अनचाहे बालों से. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं. आप आसानी से चेहरे के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकती है. लेकिन इसके लिए अपनानी होगी ये ट्रिक.

सबसे पहले आप 1 टेबल स्पून ओटमील पेस्ट लें. 2 टेबल स्पून शहद लें और 2 टेबल स्पून नींबू का रस लें.

इन सभी को मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे के उन हिस्सों पर लगाएं जहां आप अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं.

इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट तक लगा रहने दें. 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें. उसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाएं. इस नुस्खे को सप्ताह में दो से तीन बार अपनाएं, एक महीने बाद आप खुद देखेंगे अनचाहे बाल आने बंद हो गए है.

कलिंग समाचार

संपादकीय

बुधवार 10 दिसंबर 2025

शीतकालीन सत्र में बढ़ेगा सियासी तापमान

संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र शुरु होने से पहले रविवार को परंपरानुसार सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद सरकार की तरफ से दावा किया गया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष के साथ तालमेल बिठाया जाएगा। वहीं विपक्ष से उ मीद जताई गई कि वह अपने सवालों को अध्यक्ष के जरिए सदन में उठाए और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसद की मर्यादा बनाए रखे। सत्र को अकारण बाधित न करे। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा की उ मीद सरकार विपक्ष से कर रही है, असल में वही अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। क्योंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को बचाने के लिए एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ी जाएगी और संसद में इस मुद्दे को पूरे दमखम के साथ उठाया जाएगा। वहीं लालकिले के पास आतंकी हमला, दिल्ली का प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में तैयारी की कमी, आर्थिक सुरक्षा और कमजोर पड़ती विदेश नीति जैसे अहम मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि यह शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा, जिसमें केवल 15 कामकाजी दिन ही होंगे। श्री गोगोई ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने एक गंभीर बात कही है कि सरकार की तरफ ज्यादातर राजनीतिक चर्चाएं आभासी होती हैं, जबकि जनता के बुनियादी मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। मुझे उ मीद है कि सरकार चुनावों से आगे भी सोचेगी। भारत की जीडीपी वृद्धि से लेकर एसआईआर विषय तक, इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए; वरना संसद सिर्फ एक संग्रहालय जैसी संरचना बनकर रह जाएगी। दरअसल पिछले सत्रों को देखें तो मनोज झा की बात ही सच भी दिखती है कि सरकार की दिलचस्पी संसद चलाने से अधिक समय बिताने की है। अगर सत्र चलेंगे तो विपक्षी सांसद सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब ऑन रिकॉर्ड देना सरकार की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए सत्र सरकार की तरफ से ही कई बार बाधित किया जाता है। पिछले मानसून सत्र में यही हुआ। एसआईआर पर सरकार ने चर्चा नहीं होने दी और विपक्ष इसकी मांग करता रह गया। नतीजा यह हुआ कि 120 घंटों की जगह केवल 35 घंटे काम हुआ। इस बार भी ऐसा ही होने की आशंका बलवती है। क्योंकि बिहार चुनाव में धांधली के आरोप अब भी बरकरार हैं और इसके बाद प.बंगाल, उत्तरप्रदेश समेत 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रही है, उसमें बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौतें गंभीर मुद्दा बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस की शुक्रवार को ही चुनाव आयोग के साथ दो घंटे बैठक हुई, जिसमें टीएमसी सांसदों ने मु य चुनाव आयुक्त के मुंह पर ही कह दिया कि चुनाव आयोग के हाथों में खून लगा है। हालांकि आश्चर्य की बात ये है कि ज्ञानेश गुप्ता ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि कई बीएलओ एसआईआर के दबाव में अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। बिहार के बाद चुनाव आयोग एसआईआर को अन्य राज्यों में शुरु कर चुका है। भाजपा भी यह मान रही है कि वह बिहार के बाद प.बंगाल को फतह कर लेगी और बाकी राज्यों में भी उसी की जीत होगी। संसद सत्र की तारीखों का काफी पहले ऐलान इसी अति आत्मविश्वास को दिखाता है। आम तौर पर संसद सत्र की तारीखों की जानकारी ह ते-दस दिन पहले दी जाती है, लेकिन इस बार 8 नवंबर को ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने बता दिया था कि संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा। वह समय बिहार चुनावों का था। जिसमें जमीनी रिपोर्ट्स बता रहीं थी कि एनडीए के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। एसआईआर में लाखों वोटों का कटना, कानून व्यवस्था का मामला, बेरोजगारी, महंगाई इन सबके साथ 20 बरसों की नीतीश सरकार के लिए एंटी इन्कमबेंसी जैसे कारक एनडीए का नुकसान दिखा रहे थे। वहीं महागठबंधन में लोग नयी उ मीद देख रहे थे।

सत्र छोटा करके इस सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था को भी खत्म करने की तैयारी

शकील अख्तर

संसद ही एक ऐसी जगह होती है जहां केवल विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल में अच्छे- अच्छे मंत्री भी कई बार लाजवाब हो जाते थे। सदस्य तैयारी के साथ आते थे। अपने क्षेत्र के बारे में पूछे गए सवालों के साथ तथ्यात्मक सप्लीमेंट्री सवाल लाते थे। मगर अब प्रश्नकाल चलता ही नहीं। संसद का सत्र अभी कुछ साल पहले तक मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर हुआ करता था। मगर अब प्रधानमंत्री सदन में आते नहीं। प्रधानमंत्री सदन के नेता कहलाते हैं। जिस सदन से होते हैं। नरेन्द्र मोदी लोकसभा में नेता सदन हैं। मगर वे संसद में होते हुए भी सदन में नहीं आते। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मनमोहन सिंह से लेकर वाजपेयी और सभी प्रधानमंत्री पूरे संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों में रहते थे। अपने मंत्रालय से संबंधित सवालों के जवाब देते थे। और विपक्ष द्वारा उठाए गए अन्य सवालों पर भी बोलते थे। संसद सत्र खबरों से भरपूर हुआ करता था।

मगर अब संसद की प्रेस गैलरी भी खाली पड़ी रहती है। प्रधानमंत्री नहीं होते, सरकार किसी विषय पर चर्चा को तैयार नहीं होती, पीठासीन अधिकारी सत्र चलाने के बदले उसे जल्दी से स्थगित करने का तरीका अपनाते हैं, नतीजा शुरू होने के कुछ ही देर बाद सदन स्थगित। और सदन के कम समय चलने के बाद अब स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार सत्र भी कम अवधि का बुलाने लगी है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मगर सिर्फ तीन ह ते का। एक दिस बर से शुरू होगा और 19 दिस बर को खत्म। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए संसद का सत्र छोटा कर रही है।

संसद ही एक ऐसी जगह होती है जहां केवल विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल में अच्छे- अच्छे मंत्री भी कई बार लाजवाब हो जाते थे। सदस्य तैयारी के साथ आते थे। अपने क्षेत्र के बारे में पूछे गए सवालों के साथ तथ्यात्मक सप्लीमेंट्री सवाल लाते थे। मगर अब प्रश्नकाल चलता ही नहीं। संसद कवर करने वाले पत्रकारों के लिए प्रश्नकाल सबसे ज्यादा खबरों वाला और जीवंत एक घंटा हुआ करता था। हर पत्रकार उस समय वहां रहने की कोशिश करता था। उसके बाद जीरो आवर (शून्य काल) का एक घंटा। जहां सदस्य बिना पूर्व नोटिस के लोकहित का कोई मुद्दा उठा सकता था।

दोनों सदनों की प्रेस गैलरी इन दो घंटों में पूरी भरी रहती थी। मगर अब खाली ही नहीं कई बार बिना एक भी पत्रकार के भी होती है। संसद का यह रूप बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। संसद ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। मगर अब कम अवधि के संसद सत्र बुलाकर सरकार यहां भी जवाबदेही से बच रही है। संसदीय लोकतंत्र में आदर्श स्थित यह मानी जाती है कि साल में कम से कम सौ दिन संसद चले। मगर अब तो इसके आधे दिन भी नहीं चलती। और यह केवल संसद के लिए नहीं है सभी विधानमंडलों के लिए है। मगर विधानसभाओं की हालत तो और बुरी है। वहां तो ह तों के नहीं दिनों के सत्र होने लगे हैं। अगर संविधान में बजट संसद और विधानमंडलों से पास करवाने की मजबूरी नहीं होती तो शायद सरकारें सत्र बुलाती ही नहीं।

संसद और विधानमंडल ही ऐसी जगह हैं जहां सरकारों को कानूनन परंपराओं के हिसाब से जवाब देना ही होता है। मगर अब सदन स्थगित कर दो। सत्र चलने ही न दो। यह एक नया चलन शुरू हुआ है जहां सत्ता पक्ष ही सदन नहीं चलने देता। पहले विपक्ष यह काम करता था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने यूपीए के शासन काल के समय यह कहा था कि सदन नहीं चलने देना भी विपक्ष का अधिकार है। एक लोकतांत्रिक तरीका है। मगर अब उन्हीं की पार्टी सत्ता में आ गई है तो सत्ता में रहते हुए सदन नहीं चलने देती।

निश्चित रूप से ही इसका एक कारण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रभावी परफार्मेंस है। राहुल पहले भी बोलते थे। अच्छा बोलते थे। मगर पिछले साल जून से जब से राहुल नेता प्रतिपक्ष बने हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नाक में दम कर रखा है। यहां तक बोल दिया कि अगली बार जब मैं बोलूंगा तो प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठेंगे नहीं। राहुल जनता के सारे सवाल उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री वैसे तो आते नहीं मगर जब कभी आकर बैठ जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष के किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है।

प्रधानमंत्री तो पत्रकारों के सवाल के जवाब देना तो दूर उनके सवाल ही नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कान्फ्रेंस तो करते नहीं। सब प्रधानमंत्री करते थे। जिन्हें मौन कह कहकर मोदी ने सरकार बना ली वे मनमोहन सिंह भी करते थे। और हर सवाल का जवाब देते थे। मगर मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कान्फ्रेंस नहीं की। जवाब देने का सवाल ही नहीं। यह मौका आता है जब वे पत्रकारों के सामने होते हैं। परंपरा है कि सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री पत्रकारों से बात करते हैं। मोदी सामने तो आते हैं मगर अपनी बात कहकर निकल जाते हैं।

सेवाएं 11 साल में हर बार ऐसा ही किया। साल में तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र,मानसून सत्र और यह शीतकालीन सत्र। इनके पहले दिन सुबह दस बजे प्रधानमंत्री संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते थे। आम तौर पर संसद में क्या रहने वाला है, सरकार कौन से मु य विधेयक लेकर आने वाली है आदि पर।

या देश के या अन्तरराष्ट्रीय किसी बड़े तात्कालिक मुद्दे पर भी। प्रधानमंत्री पहले अपनी बात कहने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे। मगर मोदी सिर्फ अपनी बात कहकर चल देते हैं। और अपनी बात में भी विपक्ष पर आरोप। एक दिसबंर सोमवार को भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। विपक्ष पर क्या क्या आरोप लगाते हैं, क्या सलाहें देते हैं। पत्रकार कैमरे हमेशा की तरह होंगे मगर बस अब वह उ मीद किसी को नहीं बची है जो पहले थोड़ी हुआ भी करती थी कि शायद इस बार प्रधानमंत्री किसी एकाध सवाल का जवाब दे दें। अब कोई सवाल पूछता ही नहीं है। उनका इकतरफा संवाद सुनकर चला आता है। प्रधानमंत्री इस तरह गैर जवाबदेह हो सकते हैं मोदी के आने से पहले किसने सोचा था? लोकतंत्र के लिए यह कितना बड़ा खतरा है अब तो इस पर भी बात नहीं हो रही है। वह कहते हैं ना ज्यादा बड़ी तकलीफ हो जाती है तो उससे कम वाली याद नहीं आती। तो अब सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी कर दी है कि लोकतंत्र का जो मूल आधार है वोट वह भी जनता के पास रहेगा या नहीं।

एसआईआर की प्रक्रिया ने जनता के वोट के अधिकार पर ही सवाल लगा दिया है। खुद जनता से कहा जा रहा है कि वह यह साबित करे कि वह वोटर है कि नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। बिना वोटर के लोकतंत्र या कहें अपने मनचाहे वोटरों के साथ लोकतंत्र इस समय का सबसे बड़ा सवाल है।

संसद में विपक्ष यह उठाने की तैयारी कर रहा है। बीएलओ पर काम का अत्यधिक दबाव और उनकी लगातार हो रही मौतें, एसआईआर की अवधि चार दिसंबर से आगे बढ़ाने की मांग, चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण भूमिका, वोट चोरी यह सारे सवाल संसद में उठेंगे। मगर जवाब कितने का आएगा यह कहना मुश्किल है।

अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस-बैंकिंग से बदलता भारत

अरुण कुमार डनायक

अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस हमें याद दिलाता है कि बैंक केवल पूंजी निर्माण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, मौद्रिक नीति लागू करवाने और बचत को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक संस्थाएं भर नहीं, बल्कि समाज के व्यापक विकास के महत्वपूर्ण वाहक भी हैं। भारत ने वित्तीय समावेशन में नवाचार के माध्यम से दुनिया को इनोवेशन विद इंक्लूजन का प्रभावशाली मॉडल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ% ने वर्ष 2020 में 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस घोषित किया था। यह दिवस बहुपक्षीय विकास बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, जिसके माध्यम से वे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की 2030 तक प्राप्ति, सदस्य देशों के जीवन-स्तर में सुधार और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करते हैं। यह दिवस याद दिलाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और आर्थिक अवसरों जैसे एसडीजी को आगे बढ़ाने में बैंकिंग प्रणाली ही वित्तीय संसाधन और समावेशन की मूल आधारशिला है।

कई देशों ने वित्तीय समावेशन को गरीबी उन्मूलन का प्रभावी साधन बनाया है। बांग्लादेश ने माइक्रोक्रेडिट मॉडल से लाखों गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं की आय बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता पाई। प्रोफेसर मोह मद यूनुस और ग्रामीण बैंक के इस योगदान को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से स मानित किया गया। केन्या ने मोबाइल मनी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की बचत, आय और आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया। रवांडा, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पेरू ने डिजिटल बैंकिंग, समूह-आधारित ऋण और फिनटेक नवाचार के जरिए बड़ी आबादी को औपचारिक वित्त से जोड़ा। इन देशों का अनुभव दिखाता है कि जब वित्तीय पहुंच आसान होती है, तो गरीब परिवार अधिक स्थिर, आत्मनिर्भर और अवसर-संपन्न बनते हैं।

बाजार भारत में वित्तीय समावेशन की आधारशिला आज़ादी के बाद ही रखी गई थी। वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का गठन, अगले दशक में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लीड बैंक योजना जैसे निर्णायक कदमों ने बैंकिंग को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया। बैंक शाखा विस्तार नीति, स्वयं-सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के प्रसार ने वंचित वर्गों को औपचारिक वित्त से जोड़ा। 2005-06 में वित्तीय समावेशन शब्द के औपचारिक प्रयोग के साथ ही नो-फ्रिल्स खाता शुरू हुआ, जो आगे चलकर %प्रधानमंत्री जनधन खाते% का आधार बना। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से सरकारों और बैंकों के सतत प्रयासों ने वित्तीय समावेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कमजोर वर्गों को किफायती और समय पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना% के कारण 95प्रतिशत से अधिक परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जनधन-आधार-मोबाइल (जेएएम) त्रयी ने वित्तीय पहुंच को बेहद सरल बनाया। मई 2025 तक 55.44 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिनमें 56प्रतिशत महिलाएं हैं और खातों में रुपए 2.5 लाख करोड़ से अधिक जमा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) ने सीधे लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार रोका। शून्य-बैलेंस खातों में रुपे कार्ड, 2 लाख का दुर्घटना बीमा और छह महीने के सुचारु संचालन पर ओवरड्रा ट सुविधा मिलती है।

साथ ही बीमा, अटल पेंशन योजना और मुद्रा ऋण जैसी योजनाएं करोड़ों लोगों को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं। डिजिटल भुगतान की विभिन्न प्रणालियों ने बैंकिंग को जन-सुलभ बनाया और स्ट्रीट वेंडरों, लघु उद्यमियों तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान आसान कर दिया है, जिससे धन अंतरण के पारंपरिक साधन, जैसे ड्रा ट और मनीऑर्डर अब लगभग अप्रचलित हो गए हैं। %रिज़र्व बैंक% समय-समय पर नीतिगत सुधारों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत कर रहा है।

कृषि ऋण की बिना गारंटी सीमा 2 लाख तक बढ़ाई गई है, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण सीमाएं विस्तारित हुई हैं और कमजोर वर्गों की सूची भी बढ़ाई गई है। शहरी सहकारी बैंकों में महिलाओं के लिए ऋण सीमा हटाकर उन्हें अधिक लचीलापन दिया गया है। सह-ऋण व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर अधिक संस्थाओं को जोड़ा गया है।

डिजिटल भुगतान को सरल बनाने के लिए अब प्राथमिक खाताधारक की अनुमति से दूसरा उपयोगकर्ता सीमित भुगतान कर सकता है और विकलांगजन-अनुकूल भुगतान प्रणालियां विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानें बीमा डिजिटल बैंकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट अखबार बॉलीवुड न्यूज़ अपडेट अंतरराष्ट्रीय समाचार पेपर बजट विश्लेषण सेवाएं मनोरंजन समाचार युवा विशेष सामग्री वित्तीय साक्षरता के बिना समावेशन अधूरा है। %रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण और शहरी जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए %वित्तीय साक्षरता केंद्र% स्थापित किए हैं। ये केंद्र किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को वित्तीय शिक्षा और परामर्श प्रदान करते हैं, जिसमें बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान की जानकारी शामिल है; बैंक और एनजीओ मिलकर कार्यशालाएं और परामर्श चलाते हैं, जिससे समावेशन और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है। भारत में वित्तीय समावेशन की प्रमुख चिंताएं हैं - गहरी क्षेत्रीय व लैंगिक असमानताएं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नकदी-निर्भरता, कम वित्तीय साक्षरता और कमजोर ऋण अभिग यता-जिनके साथ भ्रष्टाचार व संस्थागत खामियां, बीमा उत्पादों की अनुचित बिक्री, डिजिटल धोखाधड़ी, माइक्रोफाइनेंस में अति-ऋणग्रस्तता और कठोर वसूली प्रथाएं स्थिति को और जटिल बनाती हैं। ऐसे में बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन, वित्तीय अनुशासन, नैतिकता युक्त कम खर्चीली वसूली और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना अत्यावश्यक है। वित्तीय समावेशन का भविष्य उभरती तकनीकों - एआई, ब्लॉकचेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंट एग्रीगेटर और यूनिफ़ाइड लेंडिंग इंटरफेस के प्रभावी उपयोग पर आधारित है। बैंक भी दूरस्थ क्षेत्रों के लिये हल्के और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल उत्पाद विकसित कर रहे हैं, जिससे हर नागरिक तक सुरक्षित और भरोसेमंद वित्तीय सेवाएं पहुंच सकें। आगे की प्राथमिकता डिजिटल ढांचे और वित्तीय साक्षरता के विस्तार, किसानों, मध्यम उद्योगों के लिये लचीली ऋण व्यवस्था तथा मजबूत नियामक शासन और महिला-केंद्रित नीतियों में समन्वय पर होनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस हमें याद दिलाता है कि बैंक केवल पूंजी निर्माण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, मौद्रिक नीति लागू करवाने और बचत को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक संस्थाएं भर नहीं, बल्कि समाज के व्यापक विकास के महत्वपूर्ण वाहक भी हैं।

भारत ने वित्तीय समावेशन में नवाचार के माध्यम से दुनिया को इनोवेशन विद इंक्लूजन का प्रभावशाली मॉडल दिया है। आज करोड़ों लोग, जो पहले बैंकिंग से बाहर थे, अब वित्तीय मु यधारा में आ चुके हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती, नवाचार और भरोसेमंद सेवाएं इस समावेशन को स्थायी और प्रभावशाली बनाती हैं और देश को अधिक समृद्ध, समान और सशक्त करती हैं। भविष्य का भारत तभी सच में समावेशी होगा, जब कोई भी नागरिक वित्तीय मु यधारा से बाहर न रहे। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस याद दिलाता है कि लक्ष्य सरल है- हर हाथ तक पहुंच, हर सपने को पूंजी।

नागरिक उठायें विश्व शांति के पक्ष में आवाज़

ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसके अनुसार हाल में दुनिया के अलग.अलग हिस्सों में 56 संघर्ष हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पिछले लगभग 8 दशकों में इतनी अधिक अशांति कभी नहीं रही। यह रिपोर्ट आंकड़ों में प्रकाशित हुई है लेकिन ऐसी अशांति दुनिया को किस ओर ले जा रही हैए यह बतलाने की ज़रूरत नहीं। इन संघर्षों के कारण होती तबाही से विकास पीछे रह जाता है। रिपोर्ट दुनिया भर में शांति बहाली के नये प्रयासों की जरूरत को भी दर्शाती है। संघर्षों में एक ओर देशों को अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेनाओंए गोला.बारूद आदि पर खर्च करना पड़ता है जिसके कारण नागरिकों की सुविधाओं में कटौतियां होती हैं। विस्थापनए मौतेंए भुखमरीए बीमारियांए अशिक्षा आदि युद्धों का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। स्वास्थ्यए शिक्षाए सड़कए बिजलीए पानीए आवास व्यवस्थाएं या तो सीधी लड़ाइयों में बर्बाद होती हैं अथवा उन पर खर्च करना उन देशों की सरकारों के लिये कठिन हो जाता है जो संघर्षों में शामिल होते हैं। वैश्विक शांति के बिना मानव के विकास और उसकी गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह स्थिति स य समाज के अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11 करोड़ लोग लड़ाइयों के चलते विस्थापित हुए हैं या शरणार्थी शिविरों में जीवन जी रहे हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 92 देशों की सीमाओं पर या तो युद्ध जारी हैं अथवा वहां युद्ध सदृश्य परिस्थितियां हैं। 97 देशों में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज की गयी है। रूस.यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के तीन चौथाई देशों ने रक्षा बजट में व्यापक बढ़ोतरी की है। वहां पिछले दो वर्षों से अशांति बनी हुई है। ऐसे हीए इज़रायल के साथ फिलीस्तीनए ईरान आदि की लड़ाइयों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। हज़ारों लोग मारे गये हैं और बड़ी सं या में लोग विस्थापित हुए हैं। इन युद्धों के कारण अधोरचना का विनाश सर्वाधिक होता है। सड़केंए पुलए स्कूल भवनए अस्पतालए आवासों को जो क्षति होती है वह नागरिकों का सीधा नुकसान है। युद्ध चलते तक पुनर्निर्माण स भव नहीं होता और युद्ध रुकने के बाद देशों को बदहाली से उबरने में वर्षों लग जाते हैं। युद्ध के कारण माली हालत जर्जर हो जाती है। इन देशों के नागरिकों को अपना जीवन बदहाली में काटना होता है। अशांति का असर किस प्रकार से लोगों के जीवन पर पड़ता है वह इस तथ्य के आधार पर आंका जा सकता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है ।

विविध समाचार

किसान और महिलाएं छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सामाजिक जनजीवन के महत्वपूर्ण आधार-साय

०शासकीय योजनाओं से किसान और महिलाओं का भी हो रहा चहूंमुखी विकास

जशपुरनगर ०९/१२ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के ग्राम पंचायत नारायणपुर में आयोजित किसान महतारी सज़्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुज़्यमंत्री साय ने प्रदेश के किसान एवं महिलाओं को नमन करते हुए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सज़्मानित किया। साथ ही नारायणपुर सहित आसपास क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की। इसमें नारायणपुर खेल मैदान में स्टेडियम और ज़्लड लाइट, नगर वन शिव मंदिर में मंगल भवन, नारायणपुर अटल चौक से औघड़ा आश्रम तक सोलर लाइट, नारायणपुर में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण एवं काराखेड़का में छठ घाट निर्माण की घोषणा शामिल है। इस अवसर पर विज़मंत्री ओ पी चौधरी, विधायक गोमती साय और रायमुनी भगत, प जागेश्वर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका जशपुर उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य अनिता सिंह, दुलारी सिंह एवं मलिता बाई , जनपद पंचायत अध्यक्ष दुलदुला राजकुमार सिंह, सुनील गुप्ता, मुकेश शर्मा, मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर मुज़्यमंत्री साय ने कहा कि किसान और महिलाएं छज़्ीसगढ़ के आर्थिक एवं सामाजिक जनजीवन के प्रमुख आधार है।

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्गों सहित किसान एवं महिलाओं का भी चहूंमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री किसान सज़्मान निधि, धान खरीदी योजना सहित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश की विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह 1 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। 21 माह से यह राशि दी जा रही है, यह आगे भी जारी रहेगी। महतारी वंदन योजना से अकेले जशपुर जिले में 2 लाख 29 हजार माताएं-बहनें लाभान्वित हो रहीं हैं। इन्हें अब तक 427 करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धान खरीदी जोर शोर से जारी है। सभी पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए सभी केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम किए गए है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की मान से धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही किसानों को 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान का दाम मिल रहा है। प्रदेश के करीब 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सज़्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जशपुर जिले के करीब 72 हजार किसानों को हर साल 6 हजार रूपये सज़्मान निधि दी जा रही है। जशपुर जिला संभावनाओं का गढ़ बनता जा रहा है। जशपुर की जलवायु ऐसी है कि यहाँ चाय, कॉफी, काजू, ड्रैगन ज़्रूट, मसालों और सेब की खेती के बड़े अवसर हैं। सरकार इस दिशा में तकनीक, प्रशिक्षण और अनुदान उपलज़्ध करा रही है। जशप्योर ब्रांड की पहुंच अब देश-विदेश तक हो रही है। इसके अंतर्गत महुआ लड्डू, चिरौंजी एवं अन्य वन उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जशपुर में अधोसंरचना के भी विभिन्न कार्य किया जा रहे हैं। यहां के युवाओं के तीरंदाजी सीखने की बहुत ललक है, इसको देखते हुए सन्ना पंडरापाठ में 20 करोड़ रुपए की लागत से आर्चरी अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मेडिकल कॉलेज भी निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर विज़ मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मुज़्यमंत्री साय के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया। किसान महतारी सज़्मेलन में किसान एवं महिलाओं को सज़्मानित किया गया। इसके तहत कृषक समृद्धि योजना के तहत नलकूप खनन हेतु पोलीकार्प कूजूर को 25 हजार रूपए, राजकिशोर और शिवप्रसाद साय को 18-18 हजार रूपए का अनुदान राशि का चेक प्रदान किया। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शंकर लाल टोप्पो को 01 लाख 19 हजार 65 रूपए, इंद्रप्रताप को 01 लाख 31 हजार 455 रूपए एवं रंजीत को 01 लाख 12 हजार 955 रूपए का बीमा राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राजकुमार और लवकुश को सिंचाई पाईप हेतु 50 प्रतिशत अनुदान का प्रमाण पत्र वितरण किया। इसी प्रकार नारायणपुर की कमल स्व-सहायता समूह को 4 लाख रुपए बैंक लिंकेज, ग्राम मटासी के जीवन दीप स्व-सहायता समूह को 3 लाख रुपए एवं ग्राम रानीकोज़्बो के संगम स्व-सहायता समूह को 1 लाख रुपए की बैंक लिंकेज राशि प्रदान किया गया। साथ हीसुभद्रा यादव वृन्दावती बाई, अंजू यादव एवं संगीता बाई को गाय पालन, कपड़ा दुकान एवं फास्ट फूड व्यवसाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए सज़्मानित किया गया।

रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 साल की अपहृत बच्ची बरामद, अगवा करने वाली आरोपी गिरफ्तार

रायपुर ०९/१२ (संवाददाता): जीआरपी रायपुर ने 5 वर्षीय अपहृत बच्ची को सुरक्षित बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को नादगा बीज (मध्यप्रदेश) से गिरज़्तार कर लिया है. दरअसल, 17 नवंबर 2025 को तड़के करीब 3 बजे एक दंपज़ि अपनी 5 वर्षीय बच्ची के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सो रहा था. इसी दौरान बच्ची अचानक लापता हो गई. परिजनों ने तुरंत जीआरपी रायपुर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शासनकीय रेल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जीआरपी टीम ने स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक संदिग्ध महिला बच्ची को लेकर स्टेशन से बाहर जाती दिखाई दी. इसके बाद पुलिस ने महिला की पहचान ज्योति देवी पति जसवीर सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी थाना नागदा बीज (म.प्र.) के रूप में की और उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई. कई राज्यों में की गई तलाश संदिग्ध महिला का लोकेशन ट्रेस कर पुलिस टीम ने लगातार इंदौर, उज्जैन, नागदा सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया. आखिरकार, 27 नवंबर की सुबह जीआरपी रायपुर को सफलता मिली और बच्ची को सुरक्षित बरामद करते हुए आरोपी महिला को गिरज़्तार कर लिया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला बच्ची को अपने साथ अलग-अलग स्थानों पर लेकर जाती रही. पुलिस ने तत्काल बच्ची को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया. इन धाराओं में केस दर्ज आरोपी के खिलाफ अपहरण से जुड़े गंभीर अपराधों—धारा 137(2) एवं 142 रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलज़्ध कराने की पहल

बिलासपुर ०९/१२ (संवाददाता): शीतकालीन के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलज़्ध कराने हेतु बिलासपुर-यलहंका-बिलासपुर के मध्य 5-5 फेरे के लिये साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। गाड़ी संज़्या 08261 बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु) शीतकालीन स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से दिनांक 02 दिसज़्बर 2025 से 30 दिसज़्बर 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को तथा गाड़ी संज़्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु) - बिलासपुर शीतकालीन स्पेशल ट्रेन यलहंका से दिनांक 03 दिसज़्बर 2025 से 31 दिसज़्बर 2025 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी । इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनादगाँव, डोंगरगढ़ एवं गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है गाड़ी संज़्या 08261 बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु) शीतकालीन स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को बिलासपुर से 11.00 बजे रवाना होगी तथा भाटापारा आगमन 11.38 बजे, प्रस्थान 11.40 बजे, रायपुर आगमन 12.45 बजे, प्रस्थान 12.50 बजे, दुर्ग आगमन 14.20 बजे, प्रस्थान 14.25 बजे, राजनादगाँव आगमन 14.48 बजे, प्रस्थान 14.50 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 15.13 बजे, प्रस्थान 15.15 बजे, गोंदिया आगमन 16.25 बजे, प्रस्थान 16.35 बजे, वडसा आगमन 17.57 बजे, प्रस्थान 17.59 बजे, चांदाफोर्ट आगमन 19.43 बजे, प्रस्थान 19.45 बजे, बल्लारशाह आगमन 20.20 बजे, प्रस्थान 20.30 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 21.30 बजे, प्रस्थान 21.32 बजे, मंचिर्याल आगमन 22.10 बजे, प्रस्थान 22.12 बजे, काजीपेट आगमन 23.45 बजे, प्रस्थान 23.47 बजे तथा दूसरे दिन बुधवार को चर्लपल्ली आगमन 01.53 बजे, प्रस्थान 01.55 बजे, सिकंदराबाद आगमन 02.20 बजे, प्रस्थान 02.30 बजे, लिंगमपल्ली 03.15 बजे, प्रस्थान 03.17 बजे, विकाराबाद आगमन 04.08 बजे, प्रस्थान 04.10 बजे, तांडूर आगमन 04.50 बजे, प्रस्थान 04.52 बजे, यादगीर आगमन 07.08 बजे, प्रस्थान 07.10 बजे, कृष्णा जंज़्शन आगमन 08.20 बजे, प्रस्थान 08.30 बजे, रायचूर आगमन 08.58 बजे, प्रस्थान 09.00 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 09.28 बजे, प्रस्थान 09.30 बजे, गुंटकल आगमन 11.10 बजे, प्रस्थान 11.20 बजे, गुज़ी आगमन 11.53 बजे, प्रस्थान 11.55 बजे, अनंतपुर आगमन 12.53 बजे, प्रस्थान 12.55 बजे, धर्मवरम आगमन 13.55 बजे, प्रस्थान 14.00 बजे होते हुये 18.30 बजे यलहंका पहुंचेगी इसी प्रकार गाड़ी संज़्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर शीतकालीन स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को यलहंका से 21.00 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन गुरुवार को धर्मवरम आगमन 00.28 बजे, प्रस्थान 00.30 बजे, अनंतपुर आगमन 01.03 बजे, प्रस्थान 01.05 बजे, गुज़ी आगमन 02.03 बजे, प्रस्थान 02.05 बजे, गुंटकल आगमन 03.00 बजे, प्रस्थान 03.10 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 04.13 बजे, प्रस्थान 04.15 बजे, रायचूर आगमन 04.48 बजे, 04.50 बजे, कृष्णा जंज़्शन आगमन 05.20 बजे , प्रस्थान 05.30 बजे, यादगीर आगमन 06.38 बजे, प्रस्थान 06.40 बजे, तांडूर आगमन 08.38 बजे, प्रस्थान 08.40 बजे, विकाराबाद आगमन 09.33 बजे, प्रस्थान 09.35 बजे, लिंगमपल्ली आगमन 10.30 बजे, प्रस्थान 10.32 बजे, सिकंदराबाद आगमन 11.10 बजे, प्रस्थान 11.20 बजे, चर्लपल्ली आगमन 11.43 बजे, प्रस्थान 11.45 बजे, काजीपेट आगमन 13.20 बजे, प्रस्थान 13.22 बजे, मंचिर्याल आगमन 15.10 बजे, प्रस्थान 15.12 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 16.10 बजे, प्रस्थान 16.12 बजे, बल्लारशाह आगमन 19.30 बजे, प्रस्थान 19.40 बजे, चांदाफोर्ट आगमन 19.55 बजे, प्रस्थान 19.57 बजे, वडसा आगमन 21.38 बजे, प्रस्थान 21.40 बजे, गोंदिया आगमन 23.20 बजे, प्रस्थान 23.30 बजे, तीसरे दिन शुक्रवार को डोंगरगढ़ आगमन 00.28 बजे, प्रस्थान 00.30 बजे, राजनादगाँव आगमन 00.55 बजे, प्रस्थान 00.57 बजे, दुर्ग आगमन 01.40 बजे, प्रस्थान 01.45 बजे, रायपुर आगमन 02.25 बजे, प्रस्थान 02.30 बजे, भाटापारा आगमन 03.25 बजे, प्रस्थान 03.27 बजे होते हुये 04.30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी इस शीतकालीन स्पेशल ट्रेन में 01 एसएलआरडी, 03 सामान्य, 04 स्लीपर, 02 एसी-३ इकोनामी, 08 एसी-३, 01 एसी -२ तथा जनरेटर कार सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलज़्ध रहेगी

विगत 25 वर्षों में दुर्ग जिले के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति

रायपुर ०९/१२ (संवाददाता): दुर्ग जिले के कृषि विभाग ने विगत 25 वर्षों में कृषि विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलज़्धियाँ दर्ज की हैं, जिनका सकारात्मक असर जिले की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 के दौरान खरीफऔर रबी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खरीफ फसल का क्षेत्राच्छादन 1,46,276 हेज़्टेयर तक पहुँच गया है, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है, वहीं रबी फसल का क्षेत्र 53,660 हेज़्टेयर रहा, जिसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादन के स्तर पर भी जिले का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। खरीफ फसल का कुल उत्पादन 7.20 लाख मीट्रिक टन रहा, जो 53 प्रतिशत अधिक है, जबकि रबी उत्पादन 84 हजार मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जो 43 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। उत्पादकता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है—खरीफकी उत्पादकता 4922 किलोग्राम प्रति हेज़्टेयर और रबी की उत्पादकता 1565 किलोग्राम प्रति हेज़्टेयर रही, जो क्रमश: 48 और 34 प्रतिशत अधिक है। फसल सघनता भी बढ़कर 133 प्रतिशत हो गई है, जो 25 वर्षों की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि है। किसानों को उच्च गुणवज़ा वाले कृषि आदानों की उपलज़्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2025 में 50,762 क्विंटल बीज वितरित किया गया, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार उर्वरकों का वितरण भी बढ़कर 89,632 मीट्रिक टन तक पहुंचा, जिसमें 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। खरीफ में 76,764 क्विंटल और रबी में 9,026 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया, जो पूर्व तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। इन प्रयासों से किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवज़ापूर्ण बीज उपलज़्ध होने लगे हैं, जिससे कृषि कार्यों की दक्षता और उत्पादन क्षमता में निरंतर सुधार हुआ है। वर्ष 2025 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से कुल 1,06,659 कृषकों को लाभान्वित किया गया है, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक है। यह उपलज़्धि इस बात का संकेत है कि सरकारी सहायताएँ अब अधिक व्यापक और प्रभावी रूप से किसानों तक पहुँच रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सज़्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 80,230 किसानों को 340.24 करोड़ रुपये की राशि सीधे आधार-सत्यापित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है, जिससे योजना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री ने कुज़्हार समाज के विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए

० मंगल भवन के विस्तार के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की

जशपुरनगर ०९/१२ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कुनकुरी विकास खंड के ग्राम नारायणपुर में कुज़्हार समाज के द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ, चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की।

उन्होंने कुज़्हारों को इलेज़्ट्रानिक चाक का वितरण किया। इस अवसर पर विज़ मंत्री ओ पी चौधरी, विधायक श्रीमती गोमती साय और रायमुनी भगत, पद्म जागेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शज़्भू राम चक्रवर्ती,जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका जशपुर उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य अनिता सिंह, दुलारी सिंह एवं मलिता बाई , जनपद पंचायत अध्यक्ष दुलदुला राजकुमार सिंह, सुनील गुप्ता, मुकेश शर्मा, मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण मौजूद रहे। मुज़्यमंत्री ने ग्राम गोरिया में माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुज़्हारों के लिए ग्लेजिंग यूनिट स्थापित करने घोषणा की और कुज़्हार समाज के मंगल भवन विस्तार के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। उन्होंने माँ रतनेश्वरी की जय रूद्रपाल देव की जय कर सभी को नमस्कार और जय जोहार करते हुए अपने सज़्बोधित में सबसे पहले संसार के रचियता और पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम किए और पूरे छज़्ीसगढ़वासियों के सुख, समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आज पावन ग्राम नारायणपुर में कुज़्हार समाज द्वारा आयोजित विष्णु महायज्ञ का यह पवित्र अवसर हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। इस महायज्ञ में चक्र पूजा का आयोजन विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जो हमारे कुज़्हार समाज की गहन परंपराओं को दर्शाता है। मैं इस आयोजन में पहले भी आपके बीच आता रहा हूँ। जब भी इस कार्यक्रम में आता हूँ, मुझे नयी ऊर्जा मिलती है।

चक्र पूजा न केवल मिट्टी के चक्र की आराधना है, बल्कि यह सृष्टि के निर्माण, मेहनत और रचनात्मकता का प्रतीक है। विष्णु महायज्ञ जैसे आयोजनों में आपकी भूमिका हमें याद दिलाती है कि कुज़्हार समाज प्रजापति की संतान के रूप में सृष्टि रचना में योगदान देता है और आज का यह कार्यक्रम उसकी जीवंत अभिव्यक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे कुज़्हार भाई-बहन पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिट्टी को आकार देकर आकर्षक मूर्तियों से लेकर घर के लिए उपयोगी वस्तुएँ और कलात्मक वस्तुएँ बनाते आए हैं। कुज़्हार समाज हमारी छज़्ीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आप लोग मिट्टी की कला में महारत रखते हैं। आपकी मेहनत न केवल घरेलू जरूरतें पूरी करती हैं, बल्कि तीज-त्योहारों और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को जीवंत बनाती हैं। हमारी सरकार कुज़्हार समाज की इस अनमोल विरासत को संरक्षित और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। छज़्ीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कुज़्हार भाई-बहनों के तकनीकी विकास, विज़ीय सहायता और उत्पादों की मार्केटिंग के लिए कार्यरत है। बोर्ड की योजनाओं के तहत हम परंपरागत चक्र को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहे हैं। हम इलेज़्ट्रिक चॉक (इलेज़्ट्रिक पॉटर व्हील) का वितरण कर रहे हैं, जिससे मेहनत कम होती है और उत्पादन तेजी से बढ़ता है। आज इस कार्यक्रम के दौरान में सरगुजा संभाग में हमारे कुज़्भकार भाइयों को चॉक का वितरण किया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में ग्लेजिंग यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं.

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

आरएसपी द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए कांथा सिलाई एवं फैब्रिक चित्रकारिता की द्वितीय चरण की आजीविका सृजन सीएसआर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राउरकेला ०९/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) की एक महत्वपूर्ण सीएसआर पहल के तहत कांथा सिलाई एवं फैब्रिक चित्रकारिता के द्वितीय बैच के तीन माह के आजीविका सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ एलईएडीएस, रांची के सहयोग से किया गया। नुआगाँव गाँव की 20 वंचित महिलाएँ इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। आरएसपी के मुज़्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएँ एवं सीएसआर), श्री टी जी कानेकर, उद्घाटन समारोह के मुज़्य अतिथि थे, जबकि अध्यक्ष, नुआगाँव, सुंदरगढ़, सुश्री बिस्वासी टोपनो तथा परखन विकास अधिकारी, नुआगाँव, श्री ज्योति बिकाश दास सज़्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुन्मुन मित्रा, निदेशक (एलईएडीएस), श्री ए के सिंह तथा आरएसपी, एलईएडीएस एवं ज़्लॉक कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम नुआगाँव ज़्लॉक कार्यालय में आयोजित किया गया। सभी को संबोधित करते हुए श्री कानेकर ने सतत आजीविका सृजन के लिए रचनात्मक कौशल प्रदान करने में सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। सुश्री बिस्वासी टोपनो ने क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान हेतु आरएसपी और एलईएडीएस द्वारा उठाए गए इस सार्थक पहल के लिए आभार व्यक्त किया।श्री ज्योति बिकाश दास ने गाँव की महिलाओं के लिए लाभकारी कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए सेल, आरएसपी और एलईएडीएस के प्रयासों की प्रशंसा की। सुश्री मित्रा ने प्रथम बैच की उपलज़्धियों तथा कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए परियोजना के उद्देश्य और दीर्घकालिक प्रभावों को रेखांकित किया, जो एक स्व-निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। श्री ए के सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का सफल समन्वय किया। आरएसपी-सीएसआर ने इस परियोजना को उसी ज़्लस्टर में विस्तारित किया है ताकि अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके और मौजूदा शिल्प-आधारित सूक्ष्म उद्यमों को सुदृढ़ किया जा सके। विशेषत: यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने, स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा समावेशी सामुदायिक विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से संचालित है। तीन माह के प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर महिलाओं को कांथा सिलाई एवं फैब्रिक चित्रकारिता का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे, जिससे वे परिधान, गृह सज्जा एवं विभिन्न शिल्प उत्पाद तैयार कर सकेंगी। तीसरे माह से इन उत्पादों को बाजार से भी जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षणार्थी बीपीएल परिवारों से चयनित 15-45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएँ हैं, जिनके पास बुनियादी शिक्षा और पूर्व ड्राइंग कौशल है। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम बैच की कई प्रशिक्षित महिलाओं ने स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से अपनी आय के साधन विकसित कर लिए हैं। विभिन्न मेलों और प्रदर्शनी जैसे पारबोनी बुटीक के ऑर्डर, सेल राउरकेला मेला, एज़्सआई एसएस, राँची संगोष्ठी और जिला स्तरीय मेलों में उनकी भागीदारी देखी गयी।

सरकार बदलने के बाद क्वार्टरों की मरज़्मत में 3.39 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए-माझी

भुवनेश्वर ०९/१२ (संवाददाता):मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 17 महीने पहले सज़ा में आई बीजेपी सरकार ने मंत्रियों के क्वार्टर की मरज़्मत पर 3.39 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं। भोगराई के विधायक गौतम बुद्ध दास के एक सवाल के लिखित जवाब में माझी ने कहा कि इनमें से 73.58 लाख रुपये से ज़्यादा मुज़्यमंत्री के दो क्वार्टर की मरज़्मत पर खर्च किए गए, जबकि शहर के यूनिट-II इलाके में क्वार्टर ङ्क-ढ्ढ के रेनोवेशन पर 50.10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए, और यूनिट-ङ्क इलाके में मुज़्यमंत्री को अलॉट किए गए एक और क्वार्टर VIII, D/S-1 की मरज़्मत पर 23.47 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए, उन्होंने आगे कहा।

सीएम माझी ने कहा कि शहर के यूनिट-२ इलाके में उपमुज़्यमंत्री केवी सिंह देव को अलॉट किए गए एक क्वार्टर की मरज़्मत पर 28.21 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। इसी तरह, शहर के यूनिट-२ इलाके में वन और पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यबंशी सूरज को अलॉट किए गए दो क्वार्टर के रेनोवेशन पर क्रमश: 25.74 लाख रुपये और 25.72 लाख रुपये खर्च किए गए। माझी ने आगे बताया कि शहर के यूनिट-२ इलाके में कानून और कार्य मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को अलॉट किए गए क्वार्टर के रेनोवेशन पर 20.93 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, जबकि शहर के यूनिट-२ इलाके में उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन को दिए गए क्वार्टर की मरज़्मत पर 19.6 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए।

कम लागत वाला जीवन रक्षक ऐप इसके अलावा, शहर के यूनिट-२ और यूनिट-१ इलाकों में क्रमश: पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नाइक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग के क्वार्टर के रेनोवेशन पर 18.9 लाख रुपये से ज़्यादा और 18.8 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूनिट-ङ्कढ्ढ इलाके में स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड को अलॉट किए गए क्वार्टर के रेनोवेशन पर सबसे कम 5.11 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए।

20 हज़ार से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र जल्द ही अपनी बिल्डिंग से चलेंगे

भुवनेश्वर ०९/१२ (संवाददाता): फंड की कमी, प्रशासनिक देरी और ज़मीन की अनुपलज़्धता के कारण लंबे इंतज़ार के बाद, ओडिशा में अलग-अलग जगहों से चल रहे 20,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र जल्द ही अपनी खुद की इमारतों से काम करेंगे। राज्य सरकार ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सप्लीमेंट्री पोषण, स्वास्थ्य जांच और शुरुआती बचपन की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाकी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए इमारतों का निर्माण मिशन मोड में करने का फैसला किया है।

राज्य में 74,224 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 54,074 अब अपनी खुद की इमारतों से काम कर रहे हैं, लेकिन 20,150 केंद्रों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जबकि 4,574 केंद्र स्कूल परिसर से, 10,469 सामुदायिक केंद्रों से और 3,890 किराए की जगहों से चल रहे हैं, 7,389 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए इमारतों का निर्माण चल रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने शुरू में सभी आंगनवाड़ी इमारतों का निर्माण 2019 तक पूरा करने की समय सीमा तय की थी, सूत्रों ने बताया कि इमारतों के लिए ज़मीन की उपलज़्धता, निर्माण के लिए पर्याप्त फंड और प्रशासनिक सुस्ती के कारण बहुत ज़्यादा देरी हुई।

पहले, एक आंगनवाड़ी भवन की यूनिट लागत 5.5 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे बाद में संशोधित करके 7 लाख रुपये और फिर 12 लाख रुपये कर दिया गया। बढ़ती निर्माण लागत और प्रोजेज़्ट को तेज़ी से पूरा करने की ज़रूरत को देखते हुए, राज्य सरकार ने अब लागत बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति यूनिट कर दी है। सूत्रों ने बताया, 2016 में, राज्य में 71,306 आंगनवाड़ी केंद्र थे और उनमें से 28,187 के पास अपनी इमारतें थीं। तब लक्ष्य अगले तीन सालों में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरा करना था जिसके लिए 2,377 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी। बाद में पर्याप्त फंड की कमी और ज़मीन से जुड़े मुद्दों के कारण केंद्रों को चरणों में बनाने का फैसला किया गया।

हाल ही में उपमुज़्यमंत्री प्रवती परिदा ने विधानसभा में बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग बाकी आंगनवाड़ी केंद्रों की इमारतों के निर्माण के लिए स्वतंत्र रूप से फंड देगा, जिसके बाद पंचायती राज और पेयजल विभाग, जो ज़मीन उपलज़्ध करा रहा है और काम की निगरानी कर रहा है, ने ज़िलों से इमारतों को प्राथमिकता के आधार पर, उन्नत चरणों में पूरा करने को कहा है। 15 अज़्टूबर तक पूरे होने वाले 1,993 बिल्डिंगों में से अब तक लगभग 1,461 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा चुके हैं। जिन आंगनवाड़ी केंद्र के लिए ज़मीन की पहचान अभी बाकी है, वहां कलेज़्टरों से कहा गया है कि संबंधित सब-कलेज़्टर, BDO, तहसीलदार की मौजूदगी में हर महीने रिव्यू करें, ताकि ज़मीन की पहचान की प्रोग्रेस पर नज़र रखी जा सके और फील्ड लेवल पर संबंधित समस्याओं को हल किया जा सके। स्पेशल प्रोजेज़्ट्स के डायरेज़्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने कलेज़्टरों को बताया है कि जिन मंज़ूर आंगनवाड़ी केंद्र प्रोजेज़्ट्स के लिए ज़मीन उपलज़्ध है, लेकिन टेंडर प्रोसेस शुरू न होने या बोली लगाने वालों के हिस्सा न लेने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ा है, उन्हें बढ़ी हुई यूनिट कॉस्ट पर रिवाइज्ड स्कीम के तहत लिया जाएगा।

उद्घाटन के चार महीने बाद भी बाराबती फूड कोर्ट बंद है, विक्रेता परेशान

कटक ०९/१२ (संवाददाता): बाराबती फूड कोर्ट में दुकानें मिलने का इंतज़ार कर रहे दुकानदारों में नाराज़गी बढ़ रही है, ज़्योंकि उद्घाटन के चार महीने बाद भी यह सुविधा चालू नहीं हुई है। फूड कोर्ट का उद्घाटन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने 31 अगस्त को किया था। सूत्रों के अनुसार, कटक नगर निगम ने बाराबती स्टेडियम के सामने किला मैदान की लोकप्रियता को देखते हुए यह सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई थी, जहाँ कई अस्थायी फूड आउटलेट कई सालों से कारोबार कर रहे हैं। इस कदम का मकसद स्थानीय फूड विक्रेताओं को स्थायी स्टॉल देना भी था।

इसके अनुसार, 2023 में एक कंस्ट्रज़्शन कंपनी को लगभग 8.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर काम सौंपा गया था।

यह सुविधा 2024 में पूरी हो गई, लेकिन न तो इसे चालू किया गया और न ही दुकानदारों को दुकानें अलॉट की गईं। अगस्त में उद्घाटन के बाद, दुकानदार अलॉटमेंट मिलने की उज़्मीद कर रहे थे। हालांकि, चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई और कदम नहीं उठाया गया है, जिससे दुकानदार नाराज़ हैं।

मेयर सुभाष सिंह ने कहा कि फूड कोर्ट के चारों ओर लोहे के गेट के साथ बाड़ लगाने के लिए पहले ही टेंडर जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा, सुविधा में बिजली और पानी की सप्लाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पुनर्वास केंद्र में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

संबलपुर ०९/१२ (संवाददाता):धनुपाली पुलिस ने नेताजी नगर स्थित पुनर्वास केंद्र में मानसिक रूप से विकलांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में समर्थ के दो कर्मचारियों को गिरज़्तार किया। आरोपियों में केंद्र चलाने वाले एनजीओ के सचिव हरिश्चंद्र दास और केंद्र की देखभाल करने वाली स्वागतिका प्रधान शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दोनों को केंद्र के कैदियों के साथ मारपीट करते देखा गया। परेशान करने वाले वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की एक टीम ने सोमवार को जांच के लिए केंद्र का दौरा किया। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद एनजीओ आदर्श शिशु मंदिर द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफप्राथमिकी दर्ज की गई। ज़्रैव् थबीरा महानंद ने कहा कि केंद्र चलाने वाले संगठन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

हमने कैदियों की देखभाल के लिए एक और एनजीओ को नियुक्त किया है। सात दिनों के भीतर उन्हें किसी अन्य सुविधा में पुनर्वासित करने का प्रावधान किया जाएगा। समर्थ में 30 कैदी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैदियों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने खुर्दा स्थित एक एनजीओ से तकनीकी सहायता मांगी है। फिलहाल शहर स्थित एनजीओ संबल और परिचय को कैदियों की देखभाल की जिज़्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही उन्हें शहर के बैजामुंडा स्थित एकीकृत बुनियादी ढांचा परिसर में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। संबलपुर कलेज़्टर सिद्धेश्वर बलिराम बोंडार ने कहा कि प्रशासन ने संगठन का पंजीकरण रद्द करने और उसे काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ष्केंद्र में आरोपों और पिछली घटनाओं की विस्तृत जांच करने के लिए वरिष्ठ जिला अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुनर्वास केंद्र के खिलाफआगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरएसपी द्वारा बिसरा ज़्लॉक में सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित

राउरकेला ०९/१२ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के सीएसआर विभाग द्वारा बिसरा ज़्लॉक के अलग-अलग गांवों के तीस डांस ग्रुप्स ने जमसेरा पंचायत के बीजाडीही गांव में आयोजित सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव के क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। कार्यपालक निदेशक (खान विकास एवं सीएमएलओ), श्री बी के गिरि ने समापन समारोह में मुज़्य अतिथि के तौर पर शिरकत की जबकि मुज़्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएं एवं सीएसआर), श्री टी. जी. कानेकर समारोह के सज़्मानित अतिथि थे।

इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सीएस आर), सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री आर एस बारा, उप महाप्रबंधक (सीएस आर), श्री टी.बी. टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बी जेना, उप प्रबंधक (सीएसआर), श्री एस.के. सुकुला और जमशेरा की सरपंच सुश्री बेदना ओराम, बीजाडिही की वार्ड सदस्य सुश्री जरमनी मिंज, सीएसआर के अन्य अधिकारी, एसएचजी समूह के सदस्य और गांव के बुजुर्ग उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री गिरी ने विजेताओं के साथ-साथ कार्यक्रम के प्रतिभागियों को बधाई दी और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में आरएसपी के सीएसआर विभाग के प्रयासों की सराहना की।

श्री गिरी ने प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जबकि श्री कानेकर ने विजेताओं को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया। अन्य गणमान्यों ने भाग लेने वाली टीमों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए। सारुबाहाल गांव के लक्ष्मी ग्रुप ने बिसरा ज़्लॉक नृत्य महोत्सव का चैंपियन बनकर 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और चैंपियन ट्रॉफी जीती।

उडुसु, केंडूटोला गांव के संजीता डांस ग्रुप को दूसरा पुरस्कार मिला, जिसमें 8,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी शामिल थी। तीसरा पुरस्कार कदमटोला गांव के मंगल डांस ग्रुप को 6,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर जजों को भी सज़्मानित किया गया। बाकी हिस्सा लेने वाले हर ग्रुप को 2,500/- रुपये के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। यह आयोजन आरएसपी के सीएसआर विभाग ने संतोषी मां, राधिका और आईएमके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सहयोग से आयोजित किया था। सुश्री मुनमुन मित्रा ने आए हुए लोगों का स्वागत किया, जबकि श्री टी बी टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन दिया। सीएसआर के अनुभाग अधिकारी श्री बेनेडिज़्ट एक्का ने कार्यक्रम को समन्वित किया। आयोजन को आरएसपी की सीएसआर टीम ने सुविधा प्रदान किया। आस-पास के इलाकों से बड़ी संज़्या में गांववालों ने इस शानदार नृत्य का मज़ा लिया।